



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-9] रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 अप्रैल, 2008 ई0 (चैत्र 16, 1930 शक सम्वत्) [संख्या-14

## विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक घन्टा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	-	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	221-227	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाप, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	77-83	1500
भाग 2-आज्ञाप, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	-	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	1-3	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	-	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	-	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	-	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	-	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	-	975
स्टोर्स पर्वज-स्टोर्स पर्वज विभाग का क्रोड पत्र आदि	-	1425

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## कार्मिक अनुभाग-1

## विज्ञप्ति

## नियुक्ति

05 मार्च, 2008 ई०

संख्या 677/तीस-1-2008-25(16)/2004 टी०सी०-लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा-2005 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को श्री राज्यपाल महोदय कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 के अधीन उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर वेतनमान रुपया 9000-250-10750-300-13150-350-14550/- में नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा में रखते हैं।

2. इन अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति पर उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में तैनात किया जाता है-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	तैनाती स्थान
01	श्री राजू कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री सुरेन्द्र लाल श्रीवास्तव, टाइप-II, 56, टी०वी० कॉलोनी, तेलिथरगज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश पिन-211004	रामनगर, जनपद नैनीताल
02	श्री अनिरुद्ध भट्ट पुत्र श्री गंगा प्रसाद भट्ट, सी-2/285 सेक्टर-एफ, जानकीपुरम, लखनऊ-उ०प्र०	लैन्सडाऊन, जनपद-पौड़ी गढ़वाल
03	सुश्री पारुल गैरोला पुत्री इ. एम०सी० गैरोला, 167/II, बसत विहार, पो०-न्यू फारेस्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड	देहरादून
04	श्री रीतेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री बन्धिका प्रसाद श्रीवास्तव, 1 A/9E/2, रामप्रिया रोड, 'प्रयाग' इलाहाबाद, उ०प्र० पिन-211002	अल्मोड़ा
05	श्री आशुतोष कुमार मिश्र पुत्र स्व० जय मंगल मिश्र, 383, न्यू ममफाउंडिंगज, इलाहाबाद, उ०प्र०, पिन-211002	कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल
06	श्री शिवाकान्त द्विवेदी पुत्र श्री रामानुज द्विवेदी, 11/13 बी, अनिल सोनकर लॉज, बैंक रोड, कटरा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, मवाली, जनपद नैनीताल
07	श्री निवेक श्रीवास्तव पुत्र डा० एच०एस० श्रीवास्तव, हारा सोनी पी०सी०ओ०, 523/18 बी/7, ऊँचवागदी, वेली कॉलोनी, इलाहाबाद, उ०प्र०	नैनीताल

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	तैनाती स्थान
08	श्री उदय प्रताप सिंह पुत्र श्री उग्रसेन सिंह, 190, एम०आई०जी०, आवास विकास कॉलोनी, कटरा, बस्ती, उ०प्र०, पिन-272001	काशीपुर, जनपद-ऊधमसिंह नगर
09	श्री सुधीर तोमर पुत्र श्री रामा शंकर तोमर, द्वारा रविन्दर कुमार, 58 ई/8 ई, सर्कुलर रोड, मंगानगर, नेवादा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	ऊधमसिंह नगर
10	सुश्री अनीता गुन्ज्याल, पुत्री श्री दर्जी सिंह गुन्ज्याल, द्वारा श्री धन सिंह कुटियाल, म०न०-8, टाइप-4, विकास भवन, भीमताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड	बागेश्वर
11	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री कनक सिंह, द्वारा पी०एस० रावत, इण्डियन ओवरसीज बैंक, कनखल, चौक बाजार, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	रुद्रप्रयाग

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,  
प्रमुख सचिव।

## औद्योगिक विकास अनुभाग-1

## कार्यालय ज्ञाप

19 मार्च, 2008 ई०

संख्या 1498/VII-1-08/457-उद्योग/2002-उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड में उपलब्ध महाप्रबन्धक के एक रिक्त पद के सापेक्ष सुसंगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी (नैनीताल) में तैनात श्री त्रिलोक सिंह, प्रबन्धक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से महाप्रबन्धक, वेतनमान रुपये 10,000-15,200 के पद पर नियमित रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-उक्त प्रोन्नति के कलस्वरूप श्री त्रिलोक सिंह, महाप्रबन्धक को जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी (नैनीताल) में तैनात किया जाता है।

3-श्री त्रिलोक सिंह, महाप्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन पद का कार्यभार ग्रहण कर सूचना शासन को उपलब्ध करावें।

आज्ञा से,

पी० सी० शर्मा,  
प्रमुख सचिव।



**गृह विभाग****अधिसूचना**

19 मार्च, 2008 ई०

संख्या 31/572/अ०स०/गृह/2008-उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2008) की धारा 1 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल 19 मार्च, 2008 को इस अधिनियम को प्रवृत्त करने का दिनांक नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एन० एस० नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 31/572/A.S./Home/2008, dated March 19, 2008 for general information:

**NOTIFICATION**

March 19, 2008

No. 31/572/A.S./Home/2008--In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Uttarakhand Police Act, 2007 (Act No. 01 of 2008), the Governor is pleased to appoint March 19, 2008 as the date of commencement of this Act.

By Order,

N. S. NAPALCHYAL,  
Principal Secretary.

**गृह अनुभाग-6****अधिसूचना**

प्रोन्नति

19 मार्च, 2008 ई०

संख्या 273/बीस-6/01-अगि०/2006-एतद्द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, असेष्ट अधियोजन अधिकारी (साधारण वेतनमान), सातकंठा मुख्यालय, देहरादून को अपराध अनुसंधान विभाग, देहरादून में संयुक्त निदेशक (विधि) वेतनमान रु० 12000-375-16500) के रिक्त पद पर पदोन्नत करते हुए, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

एन० एस० नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

**वित्त विभाग****अधिसूचना**

20 मार्च, 2008 ई०

संख्या 207/XXVII(8)/वाणिज्य कर(वैट)/2008-चूंकि, राज्य सरकार की राय है कि राज्य में माल आयात किये जाने के पश्चात्, राज्य में उनकी बिक्री के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम सं० 27, वर्ष 2006) के अधीन देय कर तथा अन्य देयों के अपवचन को रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, अब, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम सं० 27, वर्ष 2005) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, वित्तीय वर्ष 2008-2009 में, उनके प्रवर्तन में आने की तारीख से प्रभावी, उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट स्थानों पर जांच चौकियां स्थापित करने के सहर्ष निर्देश देते हैं :-

## तालिका

क्र०सं०	जनपद का नाम	गांव/कस्बा या नगर का नाम, जिसके निकट वाणिज्य कर जांच चौकी स्थापित की जायेगी	जांच चौकी का स्थान/रेलवे स्टेशन से निकलने वाली रोड का नाम
1	2	3	4
1.	देहरादून	रेलवे स्टेशन, देहरादून के समीप	देहरादून रेलवे स्टेशन से बाहर (पांच सौ मीटर की परिधि में)
2.	देहरादून	रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश के समीप	ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से बाहर (पांच सौ मीटर की परिधि में)
3.	हरिद्वार	रेलवे स्टेशन, हरिद्वार के समीप	हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर (पांच सौ मीटर की परिधि में)
4.	ऊधमसिंह नगर	रेलवे स्टेशन, काशीपुर के समीप	काशीपुर रेलवे स्टेशन से बाहर (पांच सौ मीटर की परिधि में)
5.	नैनीताल	रेलवे स्टेशन, हल्द्वानी के समीप	हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से बाहर (पांच सौ मीटर की परिधि में)
6.	ऊधमसिंह नगर	रेलवे स्टेशन, रुद्रपुर के समीप	रुद्रपुर रेलवे स्टेशन से बाहर (पांच सौ मीटर की परिधि में)।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 207/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2008 dated March 20, 2008 for general information :

## NOTIFICATION

March 20, 2008

No. 207/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2008--WHEREAS, the State Government is of the opinion that it is necessary so to do with a view to prevent evasion of tax and other dues payable under the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 (Act No. 27 of 2005) in respect of the sale of goods within the State after their import into the State;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 47 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 (Act No. 27 of 2005), the Governor is pleased to direct the establishment of the checkpoints in the State of Uttarakhand at the places specified in the table below with effect from the date of their coming into operation in the financial year 2008-2009:-

TABLE

Sl.No	Name of the district	Name of the village/ town or city near which Commercial Tax checkpoint will be established	Place of checkpoint/name of the road leading from railway station
1	2	3	4
1.	Dehradun	Near Railway Station, Dehradun	Outside Dehradun Railway Station (within the radius of five hundred meters)
2.	Dehradun	Near Railway Station, Rishikesh	Outside Rishikesh Railway Station (within the radius of five hundred meters)
3.	Hardwar	Near Railway Station, Hardwar	Outside Hardwar Railway Station (within the radius of five hundred meters)
4.	Udhamsingh Nagar	Near Railway Station, Kashipur	Outside Kashipur Railway Station (within the radius of five hundred meters)
5.	Nainital	Near Railway Station, Haldwani	Outside Haldwani Railway Station (within the radius of five hundred meters)
6.	Udhamsingh Nagar	Near Railway Station, Rudrapur	Outside Rudrapur Railway Station (within the radius of five hundred meters)

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,

Principal Secretary, Finance.

## गृह विभाग

## अधिसूचना

(प्रकीर्ण)

27 मार्च, 2008 ई०

संख्या 451/XX(2)/326/सुरक्षा/अधिसूचना/2003-उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 2008) की धारा 52 संपठित धारा 2 के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में उल्लिखित जिले के मेला क्षेत्र को अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

## अनुसूची

क्र०सं०	जिले का नाम	मेला का नाम	मेला का स्थान	अवधि
1.	धम्पावत	श्री पूर्णागिरी मेला, 2008	जिला पंचायत यात्री विश्राम गृह बूम से तुलीगाढ़, भैरव मंदिर, दुन्वास एवं श्री पूर्णागिरी मन्दिर के साथ ही एस०एस०बी० बैरियर बूम से मन्दिर तक लोक निर्माण विभाग के मोटर मार्ग एवं पैदल मार्ग के दोनों ओर 100-100 मीटर के मूभाग, तुलीगाढ़ से भैरव मन्दिर तक जिला पंचायत के पैदल मार्ग के दोनों ओर का 100-100 मीटर एवं तुलीगाढ़ कार्पार्किंग बैरियर से जिला पंचायत बाईपास मार्ग के दोनों ओर 100-100 मीटर का मू-भाग।	24.03.2008 से 05.06.2008 तक

आज्ञा से,

एन० एस० नपलच्याल,

प्रमुख सचिव, गृह।



In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 451/XX(2)/326/Security/Notification/2003, dated March 27, 2008 for general information :

## NOTIFICATION

(Miscellaneous)

March 27, 2008

**No. 451/XX(2)/326/Security/Notification/2003**—In exercise of the powers conferred by section 52 read with clause (m) of section 2 of the Uttarakhand Police Act, 2007 (Act No. 01 of 2008), the Governor is pleased to declare the fair area of the district as mentioned in the Schedule below :—

## SCHEDULE

Sl. No.	Name of the District	Name of the Fair	Place of the Fair	Period
1.	Champawat	Shri Poornagiri Fair, 2008	Tract of Zila Panchayat Yatri Vishram Grih Boom to Thooligar, Bhairav Temple, Thunyas and Shri Poornagiri Temple along with the S.S.B. Barrier Boom to Temple 100 mtr. on both sides of the PWD Motor road and Pedestrian way and 100 mtr. on both sides of the Zila Panchayat Pedestrian road from Thooligar upto Bhairon Temple and 100 mtrs. on both sides area from Thooligar car parking barrier to Zila Panchayat by-pass road.	24.03.2008 to 05.06.2008

By Order,

**N. S. NAPALCHYAL,**  
Principal Secretary, Home.



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक ०५ अप्रैल, २००८ ई० (चैत्र १६, १९३० शक सम्वत्)

### भाग १-क

नियम कार्य-विधियां, आन्नाए, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल सहोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

### Uttarakhand Electricity Regulatory Commission

#### NOTIFICATION

March 28, 2008

No. F-9(16)/RG/UERC/2008/ 1258 In exercise of powers conferred under section 181 of the Electricity Act, 2003, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (The Electricity Supply Code) Regulations, 2007 (Principal Regulations) namely :--

#### 1. Short Title, Commencement and Interpretation :

- (1) These Regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (The Electricity Supply Code) (First Amendment) Regulations, 2008
- (2) These Regulations extend to the whole of the State of Uttarakhand
- (3) These shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

#### 2. In Regulation 2.2 of the Principal Regulations:

- (1) After clause (2), the following shall be inserted, namely :-

- (2A) The Licensee shall examine the technical feasibility of the connection requested for and if found feasible, the licensee shall inspect and test the applicant's installation, as required of him under Rule 47 of IE Rule, 1956, in the presence of the applicant or his representative within 5 days from the date of receipt of the application form. Testing of installation shall be done as per procedure laid down in Rule 48 of IE Rules 1956 and the inspecting officer shall maintain a record of test results obtained in the form given at Annexure I(a) as required of him under Rule 47 of IE Rule, 1956.
- (2B) If upon inspection, the Licensee finds any defect, like the installation having not been completed or bare ends of conductor or joints having not been properly covered with insulating tape or that the wiring is of such nature that is dangerous to life /property etc., he shall intimate the same to the applicant on the spot under proper receipt in the form given at Annexure I(a).
- (2C) Licensee shall also record correct and full address of the premises, if not provided in the application, along with land mark near the property and also pole number from where service connection is proposed to be given. This information is necessary for future meter reading and billing.



- (2D) The applicant shall get all the defects removed within 15 days and inform the licensee in writing under acknowledgement. In case applicant fails to remove such defects or fails to inform the licensee about removal of the defects, the application shall stand lapsed and applicant will have to apply afresh.
- 2(E) Upon receipt of information from applicant about removal of defects, the Licensee shall re-inspect and test the installations within 5 days from receipt of such information and if the defects pointed out earlier are found to persist, the licensee shall again record the same in the form given at Annexure I (a) and hand over a copy of the same to applicant or his representative available on site. The application shall then stand lapsed and applicant shall be informed accordingly in writing under acknowledgement. If the applicant feels aggrieved by this action of the licensee, he may appeal to the Electrical Inspector, whose verdict in the matter will be final and binding.
- (2F) Licensee shall also ascertain whether any dues are outstanding on the premises, and if so, the licensee shall issue a demand note within 5 days from date of receipt of application form giving full details of such outstanding amount. The applicant shall be required to deposit outstanding dues within 15 days failing which his application shall lapse and the applicant shall be informed accordingly in writing under acknowledgement."
- (2) In first sentence of clause (3) the phrase "The Licensee shall examine the technical feasibility of the connection requested for and if found feasible" shall be substituted by "if on inspection no deficiency is found or the deficiencies are found to have been removed and there are no outstanding dues or the same have been cleared, the Licensee".
- (3) The following clause shall be added after clause 3, namely :-
- "(3A) In case applicant does not receive any deficiency note or demand note for the outstanding dues within 5 days from the date of application, the load applied for shall be deemed to have been sanctioned and licensee shall not deny grant of the connection on these grounds."
3. In sub-regulation 2.3.3 of the Regulation 2.3 of the Principal Regulations:
- (1) In clause (3) the words "10 days" shall be replaced by "two billing cycles"
4. In sub-regulation 3.1.2 of the Regulation 3.1 of the Principal Regulations:
- (1) In first sentence of clause (6) the words "domestic consumer" shall be replaced by "consumer"
5. In Regulation 4.1 of the Principal Regulations:
- (1) At the end of the clause (2) the following sentence shall be added, namely :-
- "The licensee may also take appropriate action, against the consumer providing such connection, under section 126 of the Act"
6. In Regulation 5.1 of the Principal Regulations:
- (1) For clause (6) of the sub-regulation (5.1.1), the following shall be substituted, namely :-
- "No case for theft shall be booked only on account of first seal on the meter missing or tampered or first instance of breakage of glass window, unless corroborated by consumption pattern of consumer and such other evidence as may be available. However any subsequent missing or tampering of seal or breakage of glass window shall be construed as suspected case of theft of energy."
- (2) For clause (7) sub-regulation (5.1.1), the following shall be substituted, namely :-
- (7) In case sufficient evidence is found to establish direct theft of energy, such officer of the licensee, as authorised for the purpose by the Commission or any other officer of the licensee, as the case may be, of the rank higher than the rank so authorised may, upon detection of such theft of electricity, immediately disconnect the supply of electricity and seize all material evidence including wires/cables, meter, service line etc. from the premises and such officer of the licensee shall lodge a complaint in writing relating to the Commission of such offence in police station having jurisdiction within twenty-four hours from the time of such disconnection.



- (7A) Within two working days from date of inspection, the licensee may also file a case against the consumer in designated Special Court as per the provisions of Section 135 of the Act. The licensee shall also conduct assessment in accordance with clause (4) of sub-regulation (5.2.3) of regulation 5.2 dealing in Un-authorized Use of Electricity (UUE) and serve on the consumer under proper receipt.
- (7B) However, on deposit or payment of the assessed amount or electricity charges in accordance with sub-regulation (7A) above, the licensee shall, without prejudice to the obligation to lodge the complaint as referred to in the sub-regulation (7) above, restore the supply line of electricity within forty-eight hours of such deposit or payment."
- (3) For clause (4) sub-regulation (5.1.2), the following shall be substituted, namely --
- (4) Where it is established that there is a case of theft of energy, such officer of the licensee, as authorised for the purpose by the Commission or any other officer of the licensee, as the case may be, of the rank higher than the rank so authorised may, upon detection of such theft of electricity, immediately disconnect the supply of electricity and seize all material evidence including wires/cables, meter, service line etc., from the premises and such officer of the licensee shall lodge a complaint in writing relating to the Commission of such offence in police station having jurisdiction within twenty-four hours from the time of such disconnection.
- (4A) The licensee may also file a case of theft in designated special court as per provisions of Section 135 of the Act. The licensee shall also conduct assessment in accordance with clause (4) of sub-regulation (5.2.3) of regulation 5.2 dealing in unauthorised use of electricity (UUE) and serve on the consumer under proper receipt. The consumer shall be required to make the payment within 7 working days of its proper receipt.
- (4B) However, on deposit or payment of the assessed amount or electricity charges in accordance with sub-regulation (4A) above, the licensee shall, without prejudice to the obligation to lodge the complaint as referred to in the sub-regulation (4) above, restore the supply line of electricity within forty-eight hours of such deposit or payment."
- (4) After sub-regulation (5.1.3), the following shall be inserted, namely --

**5.1.4 Measures to prevent diversion of electricity, theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter**

- (1) In order to reduce and prevent the menace of theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter, it is necessary to initiate preventive measures.
- (2) The licensee shall arrange inspection & certification of meters of at least 20% of total connections in his area of operation, annually.
- (3) The licensee shall arrange to provide pilfer proof meter boxes on meters of at least 20% connections every year so as to ensure that within next 5 years meters installed at all the persons' premises have pilfer proof meter boxes. The licensee shall simultaneously also review the status of service lines to ensure that it is proper and wherever required, it should be replaced to prevent theft by passing of meter.
- (4) The licensee shall intensify the effort for regular inspection of premises of persons and other persons to ensure prevention of theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter. At least 5% of total connections should be inspected annually and the provisions of the section 126 & 135 be effectively implemented.
- (5) Priority shall be given to detection of direct theft cases by the vigilance teams of the licensee, particularly in theft prone areas.
- (6) The licensee shall evolve a system and put in place within 3 months for carrying out regular monthly monitoring of consumption of high value consumer, which shall include all the HT connections and LT connections having contract demand of 25HP & above. Variations in the consumption shall be carefully analyzed. The licensee shall arrange prompt inspection of doubtful cases.

days from the date of such notice a speaking order



(3) For clause (4), sub-regulation (5 2 3) the following shall be substituted namely

- (4) Where it is established that there is a case of UJE the Licensee shall assess the energy consumption as per the assessment formula given in Annex X for the entire period during which such unauthorised use of electricity has taken place and if however the period during which such unauthorised use of electricity has taken place cannot be ascertained such period shall be limited to a period of twelve months immediately preceding the date of inspection and prepare final assessment bill on 2.0 times the rates as per applicable tariff and serve on the consumer under proper receipt. The consumer shall be required to make the payment within 7 working days of its proper receipt. The Licensee may taking into consideration the financial position and other conditions of the consumer extend the last date of payment or approve the payment to be made in instalments. The amount, the extended last date and/or time schedule of payment/instalments should be clearly stated in the speaking order. A copy of the speaking order shall also be handed over to the consumer under proper receipt."

8. The following Chapter shall be added after Chapter 6 as Chapter 7 in the Principal Regulations

#### "Chapter 7: Savings

- (1) Nothing in these regulations shall expressly or impliedly bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no regulations have been framed and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner as it considers just and appropriate

#### (2) Powers to Remove Difficulties—

If any difficulty arises in giving effect to these regulations the Commission may of its own motion or otherwise by an order and after giving reasonable opportunity to those likely to be affected by such order make such provisions not inconsistent with these regulations as may appear to be necessary for removing the difficulty

#### (3) Powers to Relax—

The Commission for reasons to be recorded in writing may relax or vary any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person "

9. The following shall be added after Annexure I of the Principal Regulations as Annexure I (a).

#### Annexure I (a)

#### Test Result Report (Refer rule 47 & 48 of IE Rules, 1956) (To be filled by representative of the licensee)

Result of Insulation Resistance to be measured on applying a pressure of 500 volts for one minute between phase conductor and earth) -

	<u>Phase 1</u> & <u>Phase-2</u> & <u>Phase-3 &amp; Earth</u>
(i) Between Phase and Earth	<u>Earth</u> <u>Earth</u>

Caution: Insulation Resistance between phase and neutral or between phases shall not be measured when any of consumer's appliances such as fans, tubes, bulbs, etc. is in circuit as results of such test would give resistance of appliance and not the insulation resistance of installation.

Certified that an Earth terminal as required under Rule 33 of IE Rules, 1956 has been provided by UPCL and this terminal has been connected with UPCL's earthing system

Following deficiencies have been found in your Electrical installation. You are requested to remove them within 15 days i.e. by \_\_\_\_\_ and inform UPCL failing which your request for new connection would lapse

- 1- \_\_\_\_\_
- 2- \_\_\_\_\_
- 3- \_\_\_\_\_
- 4- \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature of licensee representative

Name and Designation

(To be filled by applicant)

The testing of the premises has been carried out by licensee in my presence and

\* am satisfied with the testing

\* am not satisfied with the testing and may file an appeal with Electrical Inspector

It is also certified that UPCL has\*has not\* provided an Earth Terminal as per Rule 33 of E Rules, 1956 at the premises and this earth terminal has\*has not\* been connected to UPCL's earthing system

Date \_\_\_\_\_

Signature of applicant

\* Strike out which is not applicable"

- 10 The UERC (Release of New LT Connections, Enhancement and Reduction of Loads) (First Amendment) Regulations, 2007 shall be added to Appendix 1 of the Principal Regulations as Appendix 11.

Appendix 11

## Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, Dehradun

## NOTIFICATION

August 07, 2007

No. F-9(12)/UERC/2007/434—In exercise of powers conferred under section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Release of New LT Connections, Enhancement and Reduction of Loads) Regulations, 2007 (Principal Regulations), namely —

## 1 Short Title, Commencement and Interpretation :

- 1 These Regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Release of New LT Connections, Enhancement and Reduction of Loads) (First Amendment) Regulations, 2007
- 2 These Regulations extend to the whole of the State of Uttarakhand
- 3 These shall come into force on the date of their publication in the official Gazette

## 2 In clause (a) of Regulation 4(3) of the Principal Regulations

(1) at the end of clause (i), the following shall be added namely —

"Inclusion of applicant's name in the khasra or khatauni shall be sufficient for this purpose"

(2) after clause (v), the following provisos shall be inserted namely

"Provided that in case the applicant is unable to submit any of the document listed at (i) to (v) above then the applicant shall be charged thrice except for BPL consumers the amount of security as per Table 1 given in Regulation 5(10), and clause (ii) of Regulation 5(10) respectively. The owner of the premises if different from the applicant shall not be liable for payment of any due against such connection

Provided further that in cases covered under first proviso, the licensee shall have the right to review and re-determine security twice in a year i.e. on 1st April and on 1st October every year and make adjustments for the same in electricity bill for next billing cycle :

Provided further that in case the consumer fails to give security demanded by the licensee within stipulated time, the licensee may, after giving thirty days notice to the consumer as per sub-section (2) of section 47 of the Act, discontinue the supply of electricity for the period during which the failure continues."

3. In Regulation 5 of the Principal Regulations,

- (1) at the end of first sentence of sub-regulation (2), the phrase "date of receipt of application" shall be substituted by "date of receipt of application form".
- (2) in the first sentence of sub-regulation (7), in place of the phrase "from date of application giving full details" the phrase "from date of receipt of application form giving full details" shall be substituted.
- (3) in sub-regulation (8), in place of the phrase "If on inspection the deficiencies are found to have been removed" the phrase "If on inspection no deficiency is found or the deficiencies are found to have been removed" shall be substituted.
- (4) at the end of sub-regulation (8), the phrase "within 5 days" shall be substituted by "within 5 days of receipt of application form".
- (5) in the third sentence of clause (iii) of sub-regulation (10) the phrase "average consumption for 2 months" shall be substituted by "average consumption for 2 billing cycles".
- (6) in clause (b) of sub-regulation (11), the phrase "or liquidation of outstanding dues whichever is later" shall be substituted by "or liquidation of outstanding dues or the date of application whichever is later".
- (7) after clause (b) of sub-regulation (11), the following Explanation shall be added:  
*Explanation - For the purposes of this Regulation, "application" means the application complete in all respects in the appropriate form along with documents showing payment of necessary charges and other compliances.*

4. The following Regulation shall be added after Regulation 8 as Regulation 9 in the Principal Regulations:

"9. Savings :

- (1) Nothing in these regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner, as it considers just and appropriate.

(2) Powers to Remove Difficulties--

If any difficulty arises in giving effect to these regulations, the Commission may, of its own motion or otherwise, by an order and after giving reasonable opportunity to those likely to be affected by such order, make such provisions, not inconsistent with these regulations, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

(3) Powers to Relax--

The Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax or vary any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person."

By the Order of the Commission,

PANKAJ PRAKASH,  
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 14 हिन्दी गजट/288-भाग 1-क-2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।





# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक ०५ अप्रैल, २००८ ई० (चैत्र १६, १९३० शक सम्वत्)

### भाग ३

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, नगर प्रशासन, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निर्देश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), रुद्रप्रयाग

### सूचना

२५ मार्च, २००८ ई०

पत्रांक १८६/पं०-नि०नि०/२००७-०८-राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-१२२४/रा०नि०आ० जागू-२/७९४/२००८, दिनांक २४.०३.०८ के क्रम में मैं, सविन कुर्वे, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), रुद्रप्रयाग इस जनपद के स्थानीय निकाय-नगर पालिका परिषद्, रुद्रप्रयाग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निम्न पदों पर आयोग द्वारा दी गई समय सारणी के अनुसार निर्वाचन का कार्यक्रम विनिर्दिष्ट करता हूँ :-

क्र०सं०	पद का नाम	आरक्षण की स्थिति
०१	अध्यक्ष	महिला
०२	सदस्य कक्ष संख्या ०१-तिलणी	अनु० जारी
०३	०२-अपर बाजार	महिला
०४	०३-कोटेश्वर	अनारक्षित
०५	०४-बेलनी	अनारक्षित
०६	०५-स्वामी सचिदानंद नगर	अनारक्षित
०७	०६-महादेव नगर	महिला
०८	०७-पुनाड	अनारक्षित
०९	०८-भाणाधार	महिला
१०	०९-गुलाबराय	अनारक्षित

## समय-सारणी

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
28 मार्च, 2008 से 01 अप्रैल, 2008 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	02 अप्रैल, 2008 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	03 अप्रैल, 2008 (पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 16.00 बजे तक)	04 अप्रैल, 2008 (पूर्वाह्न 09.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18 अप्रैल, 2008 (प्रातः 08.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	21 अप्रैल, 2008 (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2-निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्देशित की जायेगी।

3-नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा नाम निर्देशन की वापसी एवं चिन्ह आवंटन की सभी कार्यवाही निर्वाचन अधिकारी/रिटनिंग ऑफिसर, सहायक निर्वाचन अधिकारी/असि० रिटनिंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, रुद्रप्रयाग, में सम्पन्न करायी जायेगी।

4-उक्त समय सारणी के दौरान घटने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर सभी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे।

सचिन कुर्वे,

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी  
(स्थानीय निकाय), रुद्रप्रयाग।

## जिला पंचायत, नैनीताल

## उपनियम

25 मार्च, 2008 ई०

पत्रांक 296/XII-13/97-98-(द) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 (2) (घ) (ङ) के अन्तर्गत जिला पंचायत, नैनीताल के जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में पावर मिलों, कारखानों, को नियंत्रित करने हेतु शासकीय गजट की विज्ञप्ति सं० २-4780/इक्कीस-9/90-91, दिनांक 31 अक्टूबर, 1991 में प्रकाशित हुआ है, के उपखण्ड 11, 11(1), 11(2) एवं 12(1) में निम्न प्रकार संशोधन किये जाते हैं, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे:-

## वर्तमान उपनियम

11-प्रत्येक मिल जो कच्चा, दियासलाई, लीसे की मिल, मशीन के हिस्से बनाने और मरम्मत करने की मिल, बुश बनाने और मरम्मत करने की मिल, पेन्सिल बनाने की मिल, कपड़ा, ऊन बनाने की मिल, आटा पीसने की मिल, चावल निकालने की मिल, दाल बनाने की मिल, लकड़ी चीरने की मिल, आइसक्रीम बनाने की मिल हो या अन्य मिल हो जो बिजली से चलती हो, पेट्रोल से चलती हो, स्ट्रीम गैस, डीजल, मिट्टी का तेल, क्रूड ऑयल, हवा से चलने वाली छोटी मिल मशीनों, जिसमें कि मात्र 5 श्रमिक/कर्मचारी तक कार्यरत हों, पर प्रतिवर्ष 150 रुपये प्रति मशीन यदि एक है तो, अन्यथा अधिक की दशा में इसके अतिरिक्त 50 रुपये प्रति मशीन लाइसेंस शुल्क देय होगा।

## संशोधित उपनियम

11-प्रत्येक मिल जो कच्चा, दियासलाई, लीसे की मिल, मशीन के हिस्से बनाने और मरम्मत करने की मिल, बुश बनाने और मरम्मत करने की मिल, पेन्सिल बनाने की मिल, कपड़ा, ऊन बनाने की मिल, आटा पीसने की मिल, चावल निकालने की मिल, दाल बनाने की मिल, लकड़ी चीरने की मिल, आइसक्रीम बनाने की मिल हो या अन्य मिल हो जो बिजली से चलती हो, पेट्रोल से चलती हो, स्ट्रीम गैस, डीजल, मिट्टी का तेल, क्रूड आयल, हवा से चलने वाली छोटी मिल मशीनों, जिसमें कि मात्र 5 श्रमिक/कर्मचारी तक कार्यरत हों, पर प्रतिवर्ष 300 रुपये प्रति मशीन यदि एक है तो अन्यथा अधिक की दशा में इसके अतिरिक्त 50 रुपये प्रति मशीन लाइसेंस शुल्क देय होगा।



11-(1) उपरोक्त समस्त मिलें, चाहे वे बिजली से चलती हों, पेट्रोल से चलती हों, स्ट्रीम गैस से चलती हों, डीजल, मिट्टी का तेल, क्रूड ऑयल, हवा से चलती हो, चाहे बिना शक्ति पावर से चलती हो, यदि उसमें 5 से अधिक व 10 तक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हों, तो उन्हें मिल, फैक्ट्री माना जायेगा तथा उन्हें 500 रुपये प्रतिवर्ष लाईसेन्स शुल्क देय होगा तथा घान मिल/सेलर जिनकी क्षमता 1 टन की हो, 500 रुपये प्रतिवर्ष लाईसेन्स शुल्क देय होगा तथा उससे ऊपर तक की क्षमता वाली मिल/सेलर को 2000 रुपये प्रतिवर्ष लाईसेन्स शुल्क देय होगा।

(2) उपरोक्त ऐसी सभी मिल, फैक्ट्री जिसमें 10 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी तथा 25 से कम श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हों, तो लाईसेन्स शुल्क 1500 रुपया प्रतिवर्ष तथा 25 से अधिक 50 से कम श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 2000 रुपया प्रतिवर्ष देय होगा। जिस मिल, फैक्ट्री में 50 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी तथा 100 से कम श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हों तो लाईसेन्स उस मिल, फैक्ट्री हेतु 3000 रुपया देय होगा। 100 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी और 200 से कम श्रमिक/कर्मचारियों के कार्यरत होने पर उस मिल, फैक्ट्री का लाईसेन्स शुल्क 4000 रुपया प्रतिवर्ष देय होगा। 200 से 250 श्रमिक/कर्मचारियों के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 10000 रुपया प्रतिवर्ष देय होगा, 250 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 25000 रुपया प्रतिवर्ष देय होगा।

12(1) विलम्ब शुल्क की दरे निम्न प्रकार होंगी :-

लागू शुल्क	विलम्ब शुल्क
150.00 रु0 प्रतिवर्ष	5.00 रु0 प्रतिमाह
50.00 रु0 प्रतिवर्ष	2.00 रु0 प्रतिमाह
500.00 रु0 प्रतिवर्ष	10.00 रु0 प्रतिमाह
1000.00 रु0 प्रतिवर्ष	15.00 रु0 प्रतिमाह
2000.00 रु0 प्रतिवर्ष	20.00 रु0 प्रतिमाह
3000.00 रु0 प्रतिवर्ष	30.00 रु0 प्रतिमाह
4000.00 रु0 प्रतिवर्ष	40.00 रु0 प्रतिमाह
10000.00 रु0 प्रतिवर्ष	60.00 रु0 प्रतिमाह
25000.00 रु0 प्रतिवर्ष	150.00 रु0 प्रतिमाह

11-(1) उपरोक्त समस्त मिलें चाहे वे बिजली से चलती हों, पेट्रोल से चलती हों, स्ट्रीम गैस से चलती हों, डीजल, मिट्टी का तेल, क्रूड ऑयल, हवा से चलती हो, चाहे बिना शक्ति पावर से चलती हो, यदि उसमें 5 से अधिक व 10 तक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हों, तो उन्हें मिल, फैक्ट्री माना जायेगा तथा उन्हें 1000 रुपया प्रतिवर्ष लाईसेन्स शुल्क देय होगा तथा घान मिल/सेलर जिनकी क्षमता 1 टन से ऊपर की हो तो, 2500 रुपया प्रतिवर्ष लाईसेन्स शुल्क देय होगा।

(2) उपरोक्त ऐसी सभी मिल, जिसमें 10 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी तथा 25 से कम श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हो, तो लाईसेन्स शुल्क 3000 रु0 प्रतिवर्ष तथा 25 से अधिक 50 से कम श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 4000 रुपया प्रतिवर्ष देय होगा। जिस मिल फैक्ट्री में 50 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी तथा 100 से कम श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हो लाईसेन्स शुल्क उस मिल फैक्ट्री हेतु रुपया 5000 देय होगा। 100 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी और 200 से कम श्रमिक/कर्मचारियों के कार्यरत होने पर उस मिल, फैक्ट्री का लाईसेन्स शुल्क 6000 रुपया प्रतिवर्ष देय होगा। 200 से 250 श्रमिक/कर्मचारियों के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 10000 रुपया देय होगा। 250 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 2500 रुपया देय होगा।

12(1) विलम्ब शुल्क की दरे निम्न प्रकार होंगी:-

लागू शुल्क	विलम्ब शुल्क
300.00 रु0 प्रतिवर्ष	10.00 रु0 प्रतिमाह
500.00 रु0 प्रतिवर्ष	10.00 रु0 प्रतिमाह
50.00 रु0 प्रतिवर्ष	5.00 रु0 प्रतिमाह
1000.00 रु0 प्रतिवर्ष	15.00 रु0 प्रतिमाह
3000.00 रु0 प्रतिवर्ष	30.00 रु0 प्रतिमाह
2500.00 रु0 प्रतिवर्ष	25.00 रु0 प्रतिमाह
4000.00 रु0 प्रतिवर्ष	40.00 रु0 प्रतिमाह
5000.00 रु0 प्रतिवर्ष	50.00 रु0 प्रतिमाह
6000.00 रु0 प्रतिवर्ष	60.00 रु0 प्रतिमाह
25000.00 रु0 प्रतिवर्ष	250.00 रु0 प्रतिमाह

अध्यक्ष,  
जिला पंचायत, नैनीताल।

आदेश से,  
एस0 राजू,  
आयुक्त।